Fourteenth Loksabha

Session : 7
Date : 19-05-2006
Participants : Yadav Shri Ram Kripal,Jha Shri Raghunath,Gangwar Shri Santosh Kumar,Singh Kunwar Rewati Raman,Khanduri AVSM,Maj.G Bhuwan Chandra,Meena Shri Namo Narain,Kumar Shri Shailendra,Salim Shri Mohammad,Singh Shri Mohan,Meena Shri Namo Narain,Pathak Shri Brajesh,Meena Shri Namo Narain,Singh Shri Mohan,Pal Shri Rupchand,Mishra Dr. Rajesh Kumar,Chander Kumar Shri

Title : Sh. Mohan Singh called the attention of the Minister of Environment and Forests to the need for checking water pollution in River Ganga at Varanasi and steps taken by the Government in this regard.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now, we will take up Item No.23 – Calling Attention. Shri Mohan Singhji.

SHRI MOHAN SINGH (DEORIA): Sir, I call the attention of the Minister of Environment and Forests to the following matter of urgent public importance and I request that he may make a statement thereon:

> "The need for checking water pollution in River Ganga at Varanasi and steps taken by the Government in this regard."

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRI NAMO NARAIN MEENA): Sir, the first stage of Ganga Action Plan… (*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please wait a minute. If you wish, your statement can be laid on the Table of the House. That will save time. It will form part of the proceedings.

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : मंत्री जी, आप अपना स्टेटमैंट ले कर दीजिए। इससे समय बच जायेगा।

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शकील अहमद) : यह इतना महत्वपूर्ण विाय है और आप समय बचा रहे हैं। …(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अगर आप अपना स्टेटमैंट ले करना चाहते हैं, तो उसे आप ले कर दीजिए।

…(व्यवधान)

श्री मोहन सिंह : मंत्री जी, आप अपना बयान तो दीजिए। …(व्यवधान)

श्री नमोनारायन मीना : मोहन सिंह जी, इस बारे में आपकी क्या राय है ? …(व्यवधान)

श्री मोहन सिंह : आप अपना स्टेटमैंट ले कर दीजिए।

***श्री नमोनारायन मीना:** उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से वाराणसी में गंगा नदी की सफाई के संबंध में अपना वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं -

महोदय, गंगा कार्य योजना का प्रथम चरण 1985 में शुरू किया गया था। इस चरण के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, बिहार ए वं पश्चिम बंगाल के श्रेणी एक के 25 शहरों में प्रदूाण उपशमन कार्य शुरू किए गए थे। उत्तर प्रदेश में वाराणसी सहित पांच शहरों में प्रदूाण उ पशमन कार्य शुरू किए गए थे।

गंगा कार्य योजना चरण- एक के अंतर्गत वाराणासी में 45.11 करोड़ रुपये की लागत से 34 स्कीम्स कार्यान्वित की गयीं। इस योजना के अंतर्गत प्रतिदिन 101.80 मिलियन लीटर सीवेज के शोधन की सुविधाएं सृजित की गयी हैं। इस समय, शहर में प्रतिदिन लगभग 290 मिलियन लीटर सी वेज उत्पन्न होता है। इस प्रकार शेा अशोधित सीवेज के कार्य को गंगा कार्य योजना चरण-दो के अंतर्गत चरणबद्ध तरीके से शुरू किया जाना प्रस्तावित है

यद्यपि नदी में निस्तारित होने वाले सीवेज के केवल कुछ भाग का ही वाराणसी में गंगा कार्य योजना चरण-एक के अंतर्गत दिशा परि वर्तन एवं शोधन किया गया है, परन्तु फिर भी गंगा कार्य योजना चरण-एक के शुरू होने से पहले जो नदी जल की गुणवत्ता थी, उसमें काफी सुधार हुआ है। 1986 में गंगा कार्य योजना-एक के शुरू होने के समय वाराणसी में नदी जल अधोप्रवाह में ग्रीमकालीन ऋतु में जैव रसायन आक्सीजन मांग का औसत मान 10.6 मिलीग्राम प्रति लीटर था जो र्वा 2005 में घटकर 2.3 मिलीग्राम प्रति लीटर हो गया। यह 3 मिलीग्राम प्र ाति लीटर या उससे कम के मानक मान की तुलना में कम है। इसी प्रकार नदी जल में घुलित आक्सीजन स्तर 5 मिलीग्राम प्रति लीटर या अधिक के मानक मान की तुलना में 5.9 मिलीग्राम प्रति लीटर से बढ़कर 8.3 मिलीग्राम प्रति लीटर होने की सूचना दी गयी है।

गंगा कार्य योजना के अंतर्गत वाराणसी में दूसरे चरण के कार्यों के संबंध में दो वैकल्पिक प्रस्तावों में से एक के चयन के मामले का निपटान न होने के कारण कार्य समय पर शुरू नहीं किया जा सका। एक प्रस्ताव उत्तर प्रदेश सरकार/उत्तर प्रदेश जल निगम का था और दूसरा प्रस्ताव वाराणसी नगर निगम/ एक गैर सरकारी संगठन संकट मोचन फाउंडेशन का था। विशेाज्ञ समिति की रिपोर्ट और विभिन्न स्वतंत्र विशेाज्ञों के विचारों के आधार पर मंत्रालय ने वाराणसी में कार्यान्वयन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार/ उत्तर प्रदेश जल निगम के प्रस्ताव को अंतिम रूप दिया है।

---

*The speech was laid on the table and also Placed in Library See No. LT 4361/2006.

वाराणसी में गंगा कार्य योजना चरण-दो के कार्यों के लिए वर्तमान अनुमोदित आवंटन 45.05 करोड़ रुपये है। इसके अंतर्गत प्रतिदिन 37 एमएलडी क्षमता के सीवेज शोधन संयंत्र स्थापित करने सहित 41.61 करोड़ रुपये की राशि की चार स्कीमें स्वीकृत की गयी हैं। इन स्कीमों के कार्यान्वयन में मुकदमेबाजी और लगभग डेढ़ र्वा तक माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा लगाए गए स्थगन आदेश के कारण विलंब हुआ। माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस स्थगन आदेश को समाप्त कर दिया है, परन्तु मामला अभी भी इलाहाबाद उच्च न्यायलय में न्यायाधीन है। इसी बीच स्वीकृत स्कीमों पर उत्तर प्रदेश सरकार/ उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा कार्य शुरू कर दिया गया है और 31.3.2006 तक 9.53 करोड़ रुपये (भारत सरकार का हिस्सा) खर्च किए जा चुका है।

भारत-जापान द्विपक्षीय सहयोग कार्यक्रम के अंतर्गत जापान इंटरनैशनल को-आपरेशन एजेंसी ने उत्तर प्रदेश के चार शहरों नामतः कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी और लखनऊ के सीवरेज कार्यों के संबंध में मास्टर प्लान और संभाव्यता अध्ययन रिपोर्ट तैयार करने के लिए तकनीकी सहायता अनुदान उपलब्ध करवाया है। इन शहरों में से, वाराणसी के लिए परियोजना प्रस्ताव को प्रथम प्राथमिकता के रूप में निधियन हेतु जापान बैंक फार इन्टरनैशनल को-आपरेशन को प्रस्तुत किया गया था। जेबीआईसी परियोजना को वित्तीय सहायता देने के लिए सहमत हैं और भारत सरकार और जेबीआईसी के बीच सहायता के लिए एक ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए गये हैं। परियोजना की अनुमानित लागत 552 करोड़ रुपये है। परियोजना में सीवरेज, पंपिंग स्टेशन, 200 एमएलडी वाले नए सीवेज शोधन संयंत्र का निर्माण, स्लम क्षेत्रों में सामुदायिक शौचालय परिसर, धोबी घाटों का निर्माण, स्नान घाटों को बेहतर बनाना, जन जागरूकता और भागीदारी कार्यक्रम और परियोजना के अंतर्गत सृजित संपत्तियों का उचित परिचालन और रख-रखाव के लिए स्थानीय निकाय हेतु संस्थागत विकास और क्षमता निर्माण कार्यक्रम से संबंधित स्कीमें शामिल हैं।

उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त विस्तृत परियोजना रिपोर्टों (जेआईसीए की सहायता से तैयार संभाव्यता अध्ययन रिपोर्ट के अनुसार तैयार) के आधार पर मंत्रालय ने इस परियोजना के लिए भारत सरकार के सक्षम प्राधिकरण से अनुमोदन प्राप्त करने की प्रक्रिया पहले ही शुरू कर दी है। इस परियोजना के कार्यान्वयन से शहर से नदी में गिरने वाले शेा अशोधित सीवेज से निपटने में सहायता मिलेगी और इसके परिणामस्वरूप वाराणसी में नदी की बेहतर जल गुणता प्राप्त हो सकेगी।

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : उपाध्यक्ष महोदय, गंगा नदी भारत की सबसे पवित्र नदियों में गिनी जाती है। उसमें जो काशी नगरी है, वह भारत का हृदय माना जाता cè[p9]। अनादिकाल से हमारे पुरखे गंगाजल को अपने पास धरोहर के रूप में रखते थे और जब कोई व्यक्ति दिवंगत होने की स्थिति में होता था तो उसके मुंह में गंगाजल डालने की प्रथा थी। लोगों के घर और परिवार में वर्षों तक गंगाजल सुरक्षित रखा रहता था। उसमें कोई प्रदूाण और कीड़े होने की स्थिति नहीं आती थी। जो गंगाजल भारत की पवित्रता का प्रतीक था, आज स्वयं मैला हो गया है। इससे अधिक दुर्भाग्यपूर्ण बात हमारे लिए नहीं हो सकती है। इसीलिए वर्ा 1985 में स्वर्गीय राजीव गांधी जी का ध्यान इधर गया और उन्होंने गंगा प्रदूाण को हटाने के लिए एक अभियान शुरू कराया और उसका प्रथम चरण सन् 1985 में वाराणसी में शुरू हुआ। उस पर उत्तर प्रदेश जल निगम और वाराणसी नगर निगम ने 45 करोड़ रूपए व्यय किए। उस अभियान का दूसरा चरण बहुत शीघ्र शुरू होने वाला था, लेकिन उसमें काफी विलम्ब हुआ है। सरकार का कहना है कि चूंकि परस्पर िवरोधी प्रस्ताव सरकार के पास आए, इसलिए प्रस्तावों को अनुमति देने में उसे दिक्कत हुई और इस विलम्ब का कारण प्रस्ताव देने वाली एजेंसियां हैं। मैं ऐसा मानता हूँ कि यह सरकार की बहानेबाजी है और इस सदन द्वारा नियुक्त, सदन की जांच-पड़ताल करने वाली कमेटी, जिसको हम पब्लिक एकाउण्ट्स कमेटी के नाम से जानते हैं, ने सरकार के सभी महकमों द्वारा गंगा प्रदूाण के मामले में ढिलाई बरतने और उस पैसे का अपव्यय करने के लिए कड़ी निन्दा की है। कमेटी की रिपोर्ट को सदन के सामने भी रखा गया था। मैं विश्वास करता हूं कि सरकार को लोक लेखा समिति द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदनों पर विचार करने और उस पर कार्रवाई करने का अधिकार है और कार्रवाई की जाती है। मुझे खेद है कि लोक लेखा समिति की रिपोर्ट के बा वजूद सरकार को जिस तरह से त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए थी, सरकार ने उसे नहीं किया। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि लोक लेखा समिति की उस रिपोर्ट पर सरकार क्या कार्रवाई कर रही है?

महोदय,मैं दूसरी बात यह पूछना चाहता हूं कि इस अभियान का फेज-2 वाराणसी में प्रारम्भ होने वाला था। सरकार कहती है कि 41 करोड़ रूपए का प्रोजेक्ट इसके लिए सैंक्शन कर दिया गया है। इसे न केवल स्वीकृति दे दी गयी है, वरन 31 मार्च तक इसमें से लगभग 10 करोड़ रूपए खर्च भी हो चुके हैं। मैं निठापूर्वक और शपथपूर्वक इस आदरणीय सदन के सामने कहना चाहता हूँ कि अभी हम कुछ लोग गंगा के प्रदूाण के परीक्षण के लिए वाराणसी गए थे, लेकिन दुर्भाग्य से हमारे वहां जाने के दूसरे ही दिन संकटमोचन मंदिर में एक असामयिक घटना हो गयी और कुछ उग्रवादियों ने वहां िवस्फोट करके, गंगा प्रदूाण की सफाई के लिए जो एक वातावरण बना था, उसमें बाधा डालने की कोशिश की। मैं मंत्री जी से शपथपूर्वक कहना चाहूंगा कि जो 10 करोड़ रूपए 31 मार्च तक खर्च किए जाने की बात कही गयी है, उसके लिए इस सदन की एक कमेटी वहां भेजी जाए जो इस बात की जांच करे कि वह पैसा कहां खर्च हुआ है? मैं ऐसा मानता हूँ कि उस पैसे का सरकारी अधिकारियों की मिलीभगत से कुछ बड़े लोगों ने अपवंचन कर लिया है और वाराणसी में गंगा पहले से भी अधिक प्रदूाित हो गयी है। इसके कारण उसमें स्नान करने वाले लोगों को खुजली और चर्मरोग होने लगे हैं। असी नदी और वरूणा नदी के बीच का जल, अब गंगाजल रहा ही नहीं, वह तो नाबदान का जल हो गया है। भारत सरकार कह रही है कि जापान की कोई संस्था भारत सरकार को इसके लिए कर्ज देने को तैयार है। भारत सरकार ने इसके लिए 551 करोड़ रूपए का एक प्रोजेक्ट इस विश्वास पर स्वीकृत किया है कि उस कर्ज से इसकी आपूर्ति की जाएगी। मैं इसका स्वागत करता हूँ क्योंकि सरकार बहुत-से गलत कामों के लिए भी कर्ज लेती है, यह तो एक अच्छा काम है। यदि जापान की वह संस्था कर्ज देने के लिए तैयार है तो मैं इसका स्वागत इस उम्मीद के साथ करता हूँ कि जिस मंशा से कर्ज लिया जा रहा है, उसे पूरा किया जाएगा। सरकार ने कहा है कि केवल चार शहरों के लिए यह कर्ज लिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के लिए जहां गंगा तो नहीं बहती है, लेकिन गोमती नदी का जल अंततः गंगा में ही जाता है और उसे गन्दा करता है। यह बात बिल्कुल दुरूस्त है कि गंगा को अपने पानी की आपूर्ति करने वाली नदियों और नालों की यदि सफाई नहीं हुई, तो मैं समझता हूँ कि गंगा कभी साफ नहीं हो सकती है[R10]।

कानपुर शहर गंगा को सबसे ज्यादा प्रदूाित करने वाला शहर है, जहां पर बहुत पहले टेनरीज बनी हुई हैं और उनका गंदा पानी गंगा में जाकर पूरी तरह गंगाजल को मैला और गंदा कर देता है। दूसरा शहर इलाहाबाद है और तीसरा शहर वाराणसी है। इसके अतिरिक्त भी कुछ शहर हैं, जो उत्तरांचल में हैं, जहां से गंगा निकलती है। पिछले आठ महीनों से गंगाजल गंगाजी में छोड़ा ही नहीं जा रहा है। उसका एक एक्सक्यूज था, उसे हम क्षमा करने के लिए तैयार हैं कि वहां टिहरी के डैम को ऊंचा करके उसके पानी को रोक कर वहां बिजली के उत्पादन की प्रक्रिया शुरू करनी थी। लेकिन अब टिहरी शहर डूब गया है, उस बांध के लिए जितने पानी की जरूरत थी, उसकी पूर्ति हो गई है। उसके बाद भी जितना गंगाजल हमें चाहिए, वह नहीं दिया जा रहा है। हम गंगा का पानी पिलाते हैं। दिल्ली के लोग हमसे मांग कर रहे हैं कि हमें पीने के लिए गंगाजल चाहिए, जबकि हमारे यहां अपनी सिंचाई और पीने के लिए पानी नहीं है। इस मानवीय कारण को हमें करना चाहिए, लेकिन विवशतावश हम वह नहीं कर पा रहे हैं।

हम भारत सरकार से आग्रह करना चाहते हैं कि गंगा को प्रदूाण से मुक्त करने का जो कार्यक्रम है, उसके लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम बनाना चाहिए। क्या वह समयबद्ध कार्यक्रम सरकार ने बनाया है? इसके अलावा 551 करोड़ रुपए का कर्ज लेकर इन परियोजनाओं को शुरू करने की अनुमति भारत सरकार ने दी है, किस एजेंसी के जरिए उस काम को कराया जाएगा? जब प्रथम चरण का कार्य शुरू हुआ था, उसको वाराणसी की नगरपालिका और उत्तर प्रदेश जल निगम ने शुरू किया था। मुझे यह जिम्मेदारी ओढ़ने में कोई आपत्ति नहीं है कि उस पैसे का सही उपयोग नहीं हुआ, दुरुपयोग हुआ। अगर सही उपयोग होता तो गंगा की इतनी बुरी हालत नहीं होती। आज भी गंगा में करीब-करीब 300 मिलियन लिटर सीवेज रोज आता है। हमने उसकी सफाई का, ट्रीटमेंट का इंतजाम किया है, जो कि 100 मिलियन लिटर का है। बाकी 200 मिलियन लिटर सीवेज के ट्रीटमेंट का अभी तक इंतजाम नहीं है। इसलिए मैं भारत सरकार से आग्रह करूंगा कि जो फेज सीवेज है, उसके ट्रीटमेंट के लिए भारत सरकार की क्या योजना है और इस योजना की पूर्ति वह कितने दिनों में करेगी?

ये मेरे चंद सवाल हैं, इस विश्वास के साथ मैंने इन्हें पूछा है कि पवित्र गंगा नदी जो भारत की हृदय रेखा है, उसे पवित्र बनाने के लिए भारत सरकार समयबद्ध ढंग से अपने कार्यक्रमों को कितने समय के भीतर पूरा करेगी?

उपाध्यक्ष महोदय : किसी अन्य माननीय सदस्य को समय देना सम्भव नहीं है।

...(व्यवधान)

डॉ. राजेश मिश्रा (वाराणसी) : मेरे क्षेत्र का सवाल है इसलिए मुझे मौका मिलना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं केवल प्रश्न पूछने की इजाजत कुछ माननीय सदस्यों को दूंगा। आपको भी मौका मिलेगा। सबसे पहले मैं राम कृपाल यादव जी को केवल प्रश्न पूछने की इजाजत दे रहा हूं।

श्री राम कृपाल यादव (पटना) : मैं केवल प्रश्न ही पूछूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, अभी माननीय सदस्य मोहन सिंह ने विस्तार से चर्चा की है, मैं उन बातों को नहीं दोहराना चाहता। लेकिन कुछ बातें कहना चाहूंगा। पटना संसदीय क्षेत्र का अधिकांश इलाका गंगा नदी के ठीक बगल में अवस्थित था। अगर आपको वहां जाने का मौका मिला हो, आप शायद गए भी होंगे, क्योंकि पटना सिटी गुरू गोविंद सिंह जी की जन्मस्थली है। आप जानते हैं कि पटना सिटी के गुरुद्वारे के ठीक सामने कंगन घाट अवस्थित था। लेकिन आपको अब पता नहीं चलेगा कि वह कहां है, क्योंकि धीरे-धीरे पटना शहर गंगा नदी से दूर चला गया है। यह एक चिंता का विाय है। गंगा हमारी ऐतिहासिक नदी रही है। इसके वहां नहीं रहने से कई समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। हम सब जानते हैं कि आने वाले दिनों में वहां पीने के पानी की भी भारी दिक्कत होगी, क्योंकि पानी का स्तर नीचे चला गया है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न करें।

श्री राम कृपाल यादव : मैं वही कर रहा हूं। जहां पहले पटना में पानी ही पानी था, अब हम पानी से काफी दूर हट रहे हैं। भविय में स्थिति और दुकर होने वाली है। चाहे वाराणसी हो, चाहे इलाहाबाद या पटना हो या उसके भी आगे जहां गंगा अवस्थित थी, जिसकी धारा बहा करती थी, वह पवित्र गंगा नदी थी, जो आज प्रदूाण से भरी हुई नाले का पानी जैसी लगती है। स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने जिस सोच के साथ गंगा ट्रीटमेंट प्लान की बात की थी और गंगा की सफाई की बात की lÉÉÒ[R11]।

क्या उन योजनाओं को लागू करने पर सरकार विचार कर रही है। आज गंगा बिल्कुल प्रदुाित हो गयी और पटना शहर में तो पवित्र गंगा है ही नहीं। इस बारे में सरकार क्या कोई गंभीर कदम उठाएगी जिससे गंगा की पवित्रता बरकरार रहे।

डॉ. राजेश मिश्रा : उपाध्यक्ष जी, सदन बहुत ही महत्वपूर्ण विाय पर चर्चा कर रहा है। पिछले सत्र में पब्लिक एकाउंट्स कमेटी की रिपोर्ट गंगा प्रदूाण पर आई थी और हमने उसके अगले दिन ही वाराणसी में जो गंगा प्रदूाित हो रही है, शून्य काल में इस बारे में प्रश्न किया था।

MR. DEPUTY-SPEAKER: Only question.

डॉ. राजेश मिश्रा : मैं दो-तीन प्रश्न माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं।

MR. DEPUTY-SPEAKER: Put your question.

डॉ. राजेश मिश्रा : मान्यवर, हिंदुस्तान के लोगों के लिए गंगा प्रदूाण रहित हो, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि गंगा को हम अपनी मां के समान मानते हैं।

MR. DEPUTY-SPEAKER: What is your question?

डॉ. राजेश मिश्रा : वर्ा 1984-85 में माननीय राजीव गांधी जब प्रधान मंत्री थे उस समय यूपीए की चेयरपर्सन माननीया सोनिया गांधी भी वाराणासी गयी थीं और वहां पर इन्होंने एनाउंस किया था कि गंगा को प्रदूाण मुक्त किया जाएगा और पांच साल का समय रखा गया था जिसमें वाराणासी, इलाहाबाद, पटना और कानपुर को पहले फेज में लिया गया था। जितना सीवरेज उसमें बह रहा है वह बहना बंद हो जाएगा। बाद में इस समय-सीमा को बढ़ाकर 10 साल कर दिया गया। पब्लिक एकाउंट्स कमेटी ने जो अपनी रिपोर्ट दी उसमें कहा गया कि जल निगम जो उत्तर प्रदेश की संस्था है उसके द्वारा इस दिशा में जो कार्य हुआ, उसमें लापरवाही बरती गयी जिसके कारण गंगा का प्रदूाण बढ़ गया।

दूसरे फेज में फिर क्यों उसी को सारे प्रस्ताव दिये गये। जब पब्लिक एकाउंट्स कमेटी ने जब यह कहा कि जल निगम ने लापरवाही बरती जिसके कारण यह काम 5 सालों में पूरा नहीं हो पाया तथा गंगा और ज्यादा प्रदूाति हो गयी। इस बारे में नगर-निगम ने एक प्रपोजल दिया हुआ है और थ्री-टायर सिस्टम में नगर-निगम भी एक एकाई है और उससे भी यह कार्य करवाया जा सकता है। क्या कारण है कि नगर-निगम के प्रपोजल को न लेकर सैकिंड फेज में फिर जल-निगम को ही पैसा दिया गया और 31 मार्च तक उसके 10 करोड़ रुपये खत्म भी हो गये। …(व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please sit down.

… (*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Nothing will go on record.

(Interruptions) ...*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री शैलेन्द्र कुमार।

प्रो. राम गोपाल यादव (सम्भल) : उपाध्यक्ष जी, गंगा गंगोत्री से ही गंदी होनी शुरु हो गयी है। गंगोत्री जो पर्यटक जाते हैं वे वहां पर पॉलीथीन और गंदगी छोड़ देते हैं जिसके कारण वहां का ग्लेशियर सूखने लगा है और गंगा में पानी कम होने लगा है। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि जो यात्री गंगोत्री और उनसे जुड़े हुए तीर्थस्थलों पर जाते हैं उनके पॉलीथीन और गंदगी फैलाने पर रोक लगानी चाहिए।

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल) : सर, आपने मेरा नाम पुकारा था।

उपाध्यक्ष महोदय : आपकी पार्टी के लीडर बोल चुके हैं।

श्री शैलेन्द्र कुमार : सर, गंगा का मामला है और हमने नोटिस दिया है, इसलिए हम बोलना चाहते cé[r12]।

श्री ब्रजेश पाठक (उन्नाव) : माननीय उपाध्यक्ष जी, गंगा का नाम आते ही मन में एक पवित्र भावना का अनुभव होता है। भागीरथ के साठ हजार पुरखों को तारने के बाद गंगा की शुरूआत इस सृटि में हुई।

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please put your question.

*Not Recorded

श्री ब्रजेश पाठक : मेरे संसदीय क्षेत्र उन्नाव से भी गंगा नदी हो कर गुजरती है। मैं माननीय मंत्री जी से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि इस सदन सहित माननीय पर्यावरण मंत्री को केंद्र सरकार से राज्य सरकार तक को हमने कई बार पत्र लिखे कि हमारे जनपद से गंगा निकलती है। उसके एक तरफ कानपुर और दूसरी तरफ उन्नाव शहर है। यहां गंगा नदी में भारी मात्रा में प्रदूाण है। सारी टेनरीज, जिनकी चर्चा श्री मोहन सिंह ने भी की है कि उन्नाव की छाती पर सारी टेनरीज लगी हुई हैं। वहां कच्चे चमड़े का गंदा मसाला भी गंगा नदी में जाता है और वहां पर हैंड पम्प का पानी भी पीने योग्य नहीं रह गया है। सदन सहित कई बार माननीय मंत्री जी के संज्ञान में यह बात लाई गई है कि वहां के पानी में फ्लोराइड है, यह बात पानी की जांच से भी साबित हो चुकी है। वहां बच्चे लूले और लंगड़े पैदा हो रहे हैं, जिसे वहां की माताएं बहनें समझती है कि यह देवी का प्रकोप है। जबकि वह फ्लोराइड के कारण हो रहा है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उन्नाव जनपद के पानी में फ्लोराइड के होने की पुटि हो गई है, तो वह हमारे जनपद के लोगों को शुद्ध पेयजल मिल सके, इसके लिए क्या करने जा रहे हैं।

SHRI RUPCHAND PAL (HOOGHLY): Sir, when the Ganga Action Plan was conceptualised, the erosion of the River Ganga was not such a major problem what it is today. The continuing erosion in some parts of West Bengal, like Malda, Murshidabad, Nadia, Hooghly and such other districts has caused such a major problem that the pollution is not only increasing but the progress that has already been there is made infructuous as a result of that.

So, I want to know from the Government, whether the Government will have a re-look at the project itself and in the framework of its concept erosion is also included so that the pollution that is there is not increased by this erosion.

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूडी (गढ़वाल) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यहां गंगा नदी में प्रदूाण के बारे में चर्चा हो रही है। गंगा का नाम, जो कि देव प्रयाग से शुरू हो जाता है, उससे पहले भागीरथी और अलकनंदा दो प्रमुख नदियां हैं जो देव प्रयाग में मिलती हैं, उसके बाद इसे गंगा नाम मिलता है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं और पहले वक्ताओं ने भी कहा है कि गंगा सिर्फ नीचे ही मैली नहीं हो रही है। श्री मोहन सिंह ने भी कहा है कि अनेकों नाले इसमें मिलते हैं, लेकिन यह नदी शुरूआत से ही गंदी होने लगती है। अभी श्री रामगोपाल यादव जी ने गंगोत्री के बारे में कहा। भागीरथी ग्लेशियर से दूसरी तरफ जोशीमठ साइड से बद्रीनाथ साइड से यमुनोत्री आती है और ये दोनों देवप्रयाग में मिलती हैं। लेकिन देवप्रयाग आते-आते यह नदी गंदी होने लगती है। उसका मुख्य कारण यह है कि दोनों रास्तों में यात्रियों की संख्या अधिक होती है। उसके साथ ही पोलीथीन भी एक बीमारी है और उचित शौचालय भी उपलब्ध नहीं है। गंगा, भागीरथी, अलकनंदा, मंदाकनी केदारनाथ की तरफ जाती है तो उनके किनारों को शौचालयों के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या आप इस समस्या से अवगत हैं कि गंगा नदी हरिद्वार से पहले ही गंदी होती जा रही है? क्या आप इस बारे में कोई विशेा आयोजन कर रहे हैं? क्या आप पोलीथीन को बंद करने का और उचित शौचालयों का बंदोबस्त करने का कोई प्र ाबंध करने की योजना बना रहे हैं ताकि गंगा नदी को गंदा होने से रोका जा सके?

प्रो. चन्द्र कुमार (कांगड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, श्री मोहन सिंह जी ने बहुत अच्छे विाय पर ध्यानार्काण प्रस्ताव रखा है। मैं इस विाय के बारे में माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार के पास कोई ऐसी लांग टर्म प्लानिंग है कि जहां से गंगा नदी शुरू होती है वहां से इसकी आखिरी सीमा तक जितने शहर हैं उनकी सीवरेज प्रणाली और उसके क्षेत्र में जितने भी नाले गिरते हैं, उनके लिए कोई एक्शन प्लान है। गंगा क्लिनिंग एक्शन प्लान स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने बनाया था, उसे क्यों बंद कर दिया गया cè[i13]? उसके बदले में कौन सा ऐसा कार्यक्रम है जो बड़ी-बड़ी रीवर्स को क्लीनिंग आपरेशन के जरिए जितने कैचमैंट एरियाज में शहर बसे हैं, उनका सीवरेज सिस्टम ठीक कर सकें। उसके लिए सरकार ने कौन से कदम उठाए हैं? सरकार चरणबद्ध तरीके से उन प्रोजैक्ट्स को कब पूरा करने वाली है? …(व्यवधान)

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, इसमें मेरा नाम भी जोड़ लिया जाए। मैं हर महीने गंगा जी जाता हूं। मैं गंगा की सफाई की बात कह रहा हूं। मुझे और कुछ नहीं कहना है। ...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदयः आप स्लिप भेज दीजिए। हम एसोसिएट करवा देंगे।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदयः जो-जो चाहते हैं, उन्हें एसोसिएट करवा देंगे।

श्री शैलेन्द्र कुमार : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने बहुत जद्दोजहद के बाद, मेहरबानी करके बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। इलाहाबाद तीर्थों का राज प्रयागराज है। आप भली-भांति जानते हैं कि वहां अभी माघ मेला सम्पन्न हुआ। आपको यह भी मालूम है कि गंगा का पानी इतना प्रदूति है कि वहां जितने भी देश भर के साधु-संत गए, वे अनशन पर बैठ गए। उनकी मांग थी कि टिहरी बांध से पानी खोला जाए। उत्तरांचल सरकार जानबूझ कर वहां पानी बंद रखती है। प्रदूाण के लिए हमारी पार्टी के पूर्व विधायक श्री गोपाल दास यादव ने डीएम के यहां अनशन किया। तब जाकर पानी खुला है। भारत-जापान द्विपक्षीय सहयोग कार्यक्रम के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के चार महानगरों कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, लखनऊ को लिया गया है। मास्टर प्लान और अध्ययन रिपोर्ट में बहुत कुछ कहा गया है। वहां सीवरेज प्लांट गऊघाट में लगा है। वह रेवती रमण जी का निर्वाचन क्षेत्र भी है। वहां का जल निगम जापान सरकार के कोलैबरेशन से बना है। गंगा एक्शन प्लान में कहा गया है कि स्लम क्षेत्रों में सामुदायिक शौचालय, परिसर, घोबी घाटों का निर्माण, स्नान घाटों का निर्माण किया जाए लेकिन अभी तक उस पैसे का पूरी तरह सदुपयोग नहीं हो पाया है। इसके बावजूद पैसे का कहीं अता-पता नहीं है। आने वाले वर्ा में इलाहाबाद में कुम्भ का मेला लगने वाला है जिस में देश-विदेश से तमाम सैलानी आते हैं। क्या उस पैसे से गंगा के प्रदूाण को साफ कराने की सरकार की कोई योजना है?

श्री रघुनाथ झा (बेतिया) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा नाम भी जोड़ दिया जाए।

उपाध्यक्ष महोदयः रघुनाथ जी का नाम एसोसिएट कर लें और सलीम जी का भी कर दें।

मोहम्मद सलीम (कलकत्ता-उत्तर पूर्व) : मैं प्रदूाण के बारे में केवल सवाल पूछ रहा हूं। गंगा हमारे देश की सभ्यता, संस्कृति का प्रतीक है। वह हमारे धर्म, समाज, अर्थ नीति और नगर सभ्यता से जुड़ी है। उत्तर भारत खास तौर पर गंगा से घिरा हुआ है। हमारे यहां हिप्पोक्रेसी है। हम सोचते हैं कि अगर हम वहां स्नान करेंगे तो पवित्र होंगे लेकिन सबसे ज्यादा अपवित्र करने में हमारा योगदान रहता है। चूंकि मैं बंगाल से आता हूं। गंगा सागर सभी लोग जाते हैं। पूरे देश का प्रदूाण बंगाल की तरफ धकेल दिया जाता है। केवल राजनीतिक और सांस्कृतिक प्रदूाण नहीं जो फिजिकल प्रदूाण है ...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदयः आप प्रश्न पूछिए।

मोहम्मद सलीम : मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि जो गंगा एक्शन प्लान बनाया गया था, इसे मॉनिटर करना पड़ेगा। आज की स्थिति में जो नए किस्म के प्रदूाण हो रहे हैं, उसकी रोकथाम के लिए सरकार क्या उपाय कर रही है? हरिद्वार में बिल्डिंग्स का डैमोल्यूशन हो रहा है। वहां सारा कूड़ा-करकट फेंका जा रहा है। बनारस में पानी में उतर नहीं सकते हैं। गंगा की अंतिम पंक्ति में जो हैं, उनकी तरफ देख कर सरकार क्या बंदोबस्त कर रही है?

श्री संतोा गंगवार (बरेली) : गंगा एक्शन प्लान बीस साल से चल रहा है, अभी कितना समय और लगेगा? वर्ा 1985 से अब तक बीस साल हो गए हैं, अभी कितना समय और लगेगा ताकि हमें जमीन पर कुछ होता हुआ नजर आए?

श्री मोहन सिंह : जब कभी ध्यान आर्काण प्रस्ताव आता है तब उसका उत्तर भारसाधक कैबिनेट मंत्री देते हैं। लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि माननीय मंत्री जी को इसका उत्तर देने के लिए लगा दिया गया जिनका पॉलिसी मीटिंग में कितना योगदान है, मैं समझता हूं। यह सरकार की लापरवाही और गैरजिम्मेदारी है। मैं ऐसी मान्यता लेकर बैठ रहा हूं कि सरकार गंगा सफाई अभियान में कतई गंभीर नहीं है। इसकी अगंभीरता का यह परिणाम है कि माननीय राज्य मंत्री जी को खड़ा कर दिया जो इस विाय के बारे में कुछ जानते नहीं हैं।

MR. DEPUTY-SPEAKER: The hon. Minister is giving the reply on behalf of the Government.

... (*Interruptions*)

श्री मोहन सिंह : मैं इसका प्रोटेस्ट करता हूं, मेरा प्रोटेस्ट दर्ज किया जाए।

MR. DEPUTY-SPEAKER: The hon. Minister knows everything.

… (*Interruptions*)

श्री नमोनारायन मीना : सबसे पहले माननीय सदस्य ने जो एतराज किया है, इसके संबंध में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में से कोई भी जवाब दे सकता है। अगर संबंधित विभाग का मंत्री नहीं है तो दूसरा मंत्री भी सरकार की तरफ से जवाब दे सकता है।

श्री रेवती रमन सिंह (इलाहाबाद) : माननीय सदस्य, श्री मोहन सिंह जी ने जो बात कही है, उसके बारे में सब जानते हैं कि कोई भी मंत्री जवाब दे सकता है। लेकिन यहां इतना गंभीर सवाल उठाया गया है इसलिए सरकार को गंभीरता जवाब देना चाहिए था लेकिन उसका जवाब देने के बजाय मंत्री जी गायब हो गए जबकि वे सुबह यहां मौजूद थे। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि गंभीरता नाम की चीज इस सरकार में नहीं है। गंगा एक्शन प्लान जब लागू हुआ उसके बाद गंगा का पानी ज्यादा गंदा हो गया है।

ग्रामीण विकास मंत्री (डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह) : आपको संतुट कर दिया जाएगा।

श्री नमोनारायन मीना : माननीय सदस्य श्री मोहन सिंह जी बहुत महत्वपूर्ण कॉलिंग अटैन्शन मोशन लाए हैं। मैं उन माननीय सदस्यों को बहुत धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इसमें भाग लिया है और उनका भी धन्यवाद करता हूं जो इस चर्चा में भाग लेना चाहते थे।

जहां तक गंगा का सवाल है। वर्ा 1985 में गंगा एक्शन प्लान चालू किया गया था। इस एक्शन प्लान के बारे में जिस समय सोचा गया था उस समय, यानी वर्ा 1985 में गंगा की स्टडी की गई थी। जब इसकी रिपोर्ट आई तब इसमें 1340 एम.एल.डी. पॉल्यूशन लोड था और 882 एम.एल.डी. गैप फर्स्ट में प्लेन किया गया था। मेरे कहने का मतलब है कि उस समय 65 प्रतिशत लोड का हैंडल फाइनेंशियल क्रंच के कारण किया गया था। जब सैकिण्ड फेस आया तब उसमें 780 एम.एल.डी. का प्रावधान रखा गया। अब गंगा पर करंट पॉल्यूशन लोड 2538 एम.एल.डी. है।

श्री रेवती रमन सिंह : पहले कितना था?

श्री नमोनारायन मीना : वर्ा 1985 में 1340 एम.एल.डी. था और 452 करोड़ रुपए फंड स्वीकृत किया गया था।

श्री रेवती रमन सिंह : इसका मतलब है कि यह फिर बढ़ गया।

MR. DEPUTY-SPEAKER: Silence please. Please do not disturb.

… (*Interruptions*)

श्री नमोनारायन मीना : पॉल्यूशन कंट्रोल का सीधा संबंध जनसंख्या से है। अपर स्ट्रीम में जनसंख्या बढ़ती जा रही है और पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है। अभी पॉल्यूशन लोड 2538 एम.एल.डी. है। अभी गैप फर्स्ट और सैकिण्ड लिया है लेकिन इसके बावजूद 876 एम.एल.डी और बच गया है क्योंकि फाइनेंशियल क्रंच हमेशा रहता है। इसके लिए पहले फर्स्ट फेस में 452 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया था। अगर दूसरे फेस में पूरे पॉल्यूशन लोड को एक साथ लें तो आज की तारीख में लगभग 1300 करोड़ रुपए SÉÉÉÊcA[v14]।

माननीय मोहन सिंह जी ने बनारस के बारे में सवाल उठाया। मैं बताना चाहता हूं कि हमारा फर्स्ट फेज वर्ा 2000 में कम्पलीट हुआ। यह वर्ा 1985 में चालू हुआ था और वर्ा 2000 में कम्पलीट करके इसे क्लोज कर दिया गया। क्योंकि इसमें जो 261 स्कीमें लाई गईं थी, उनमें से 259 पूरी हो गईं। केवल मुंगेर और पटना की स्कीमें समय पर पूरी नहीं हो पाईं। इसके बारे में स्टेट गवर्नमैन्ट को बोला गया कि इन्हें आप पूरी कीजिए और ये दोनों भी पूरी होने के आसपास हैं। इस फर्स्ट फेज के बाद प्लानिंग कमीशन ने हमारे मंत्रालय को कहा कि इसका कॉस्ट बैनिफिट एनालैसिस कराइये। हमारे मंत्रालय ने हार्वर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल डवलपमैन्ट और हमारे देश के कुछ प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस को इसमें लगाया। उन्होंने वर्ा 2000 में अपनी रिपोर्ट पेश की। उस रिपोर्ट में उन्होंने कहा कि कॉस्ट बैनिफिट एनालैसिस के हिसाब से विश्व की मेजर नदियां जिनमें थेम्स, डेन्यूब और राइन प्रमुख हैं, यदि हम उनसे कम्पेयर करें तो उसमें टाइम टेकन और कॉस्ट के हिसाब से गंगा का फर्स्ट फेज फेवरेबल साबित होता है। इंटरनेशनल हार्वर्ड इंस्टीट्यूट ने इस तरह की रिपोर्ट दी है। …(व्यवधान) आप सुनिये, हम अभी दे रहे हैं।

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी : यह ठीक नहीं है …(व्यवधान)

डॉ. शकील अहमद : आप पहले जवाब सुन लीजिए, उसके बाद बोलिये।…(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप जवाब खत्म होने दीजिए।

… (*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Except the speech of the Minister, nothing should be recorded.

(Interruptions) ...*

---

*Nor Recorded

श्री नमोनारायन मीना : गंगा के पानी को मॉनीटर करने के लिए 27 मॉनीटरिंग स्टेशंस बनाये गये हैं और ये मॉनिटरिंग स्टेशंस सैन्ट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, आई.आई.टी., कानपुर और बी.एच.ई.एल. जैसे इंडिपैन्डैन्ट संस्थान देख रहे हैं। वे जो क्वालिटी कंट्रोल करते हैं और फिगर्स देते हैं, उनके बारे में मैं सदन को अवगत कराना चाहता हूं। इसमें दो पैरामीटर्स मुख्य होते हैं, प्रथम डी.ओ., यानि डिसोल्व्ड ऑक्सीजन और बी.ओ.डी.। ये मुख्य पैरामीटर्स होते हैं, जो दिखाते हैं कि वाटर क्वालिटी कैसी है। उसमें कितनी ऑक्सीजन है। इन दोनों मापदंडों के आधार पर मैं आपको बताना चाहता हूं। 1986 में ऋाकिेश में डी.ओ. 8 था। वर्ा 2005 में 8.50 है, यानी यह अच्छा हुआ है। क्वालिटी बैटर हुई है। 1986 में ऋाकिेश में बी.ओ.डी. 1.7 था, वर्ा 2005 में यह एक है। यह तीन से कम होना चाहिए।

प्रो. राम गोपाल यादव : बनारस का क्या हाल है?

श्री नमोनारायन मीना : मैं सीधे बनारस पर आ जाता हूं। वाराणसी अपस्ट्रीम में बी.ओ.डी. वर्ा 1986 में 10.1 मिलीग्राम प्रति लीटर था। यह तीन से नीचे होना चाहिए। वर्ा 2005 में यह दो है। यानी तीन से कम है। क्वालिटी बैटर है। …(व्यवधान)

प्रो. राम गोपाल यादव : ये सारे तथ्य फर्जी हैं, बिल्कुल गलत हैं। इनमें एक भी सही नहीं है, सब गलत हैं। आप यदि आज गंगा के पुल से निकलते हैं तो नाक बंद करनी पड़ती है। यह स्थिति हो गई है। यह आपके तथ्यों के खिलाफ है। आप इसकी जांच कराइये और जो लोग आपके पास गलत तथ्य दे रहे हैं, उन अधिकारियों के खिलाफ आप कार्रवाई कीजिए[R15]।

Sir, it is absolutely wrong. … (*Interruptions*)

श्री नमोनारायन मीना : ये सारे जो डॉटा हैं, देश के रेप्युटेड इंस्टीट्यूशंस क्वॉलिटी कंट्रोल करते हैं, उनके द्वारा पायी गई हैं, जैसे बीएचईएल है, आई.आई.टी. कानपुर है, सेन्ट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, टॉक्सिक्लोजी सेंटर, लखनऊ है। ये चार संस्थान हैं। ये उनको मोनीटर कर रहे हैं।

श्री राम कृपाल यादव : मैंने पटना के बारे में पूछा था।…(व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Ram Kripal Yadav, please do not disturb.

… (*Interruptions*)

श्री नमोनारायन मीना :एक प्वाइंट यह है कि जहां गंगा अच्छी है, साफ-सुथरी है, वह ऋाकिेश, हरिद्वार, गोमुख और कन्नौज की अपस्ट्रीम तक है, उसके बाद प्रॉब्लम चालू होती है। वह है कन्नौज डाउन स्ट्रीम, बीओडी तीन होना चाहिए लेकिन वहां साढ़े चार है, इसका मतलब क्वॉलिटी खराब है। दूसरी, कानपुर अपस्ट्रीम 4.3 है, क्वॉलिटी खराब है लेकिन पहले के मुकाबले 1986 में 7.2 था, अब 4.3 है। कानपुर डाउन स्ट्रीम 1986 में बीओडी 8.6 था, अब 5.4 है। कम हुआ है।…(व्यवधान)

श्री रघुनाथ झा : हमारे बिहार के बारे में माननीय मंत्री जी ने क्या किया है, वह बताएं।...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय :रिप्लाई पहले खत्म हो जाने दीजिए।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय :झा जी, रिप्लाई तो पहले खत्म होने दें।

श्री नमोनारायन मीना :अभी बताते हैं।...(व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Mr. Minister, you are requested to address the Chair.

... (*Interruptions*)

.SHRI C.K. CHANDRAPPAN (TRICHUR): Sir, we should be allowed to ask questions. ... (*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Let him finish his reply.

... (*Interruptions*)

श्री नमोनारायन मीना : जोहमारा समस्या एरिया है, वह कन्नौज से लेकर इलाहाबाद अपस्ट्रीम तक है। इसमें काली नदी है और राम गंगा नदी है, ये दोनों मिलती हैं। इनमें से कुछ इंडस्ट्रीज का पोल्यूशन आता है, कुछ एक्शन भी लिया गया है। अभी हमने 51 इंडस्ट्रीज आइडेंटिफाइ की हैं और 23 क्लोज कर दी हैं और कुछ में ट्रीटमेंट प्लांट लगा दिया है। यह प्रॉब्लम एरिया है। बाकी और जगह इम्प्रूवमेंट हुआ है, जो आंकड़े बताते हैं।...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय :पहले रिप्लाई खत्म हो जाने दीजिए।

...(व्यवधान)

श्री नमोनारायन मीना :अभी मोहन सिंह जी के जो सवाल थे, उन पर वाराणासी में अभी गंगा फेज II का कार्य चल रहा है। उसमें आपने कहा कि इतने पैसे नहीं दिये, वे हमें बताएं कि हमारे यहां से रिलीज हुए हैं, किस काम में उन्होंने लगाये। मैं आपको अभी बताता हूं लेकिन जापान बैंक ऑफ इंटरनेशनल कोआपरेशन से वाराणासी के लिए 552 करोड़ समथिंग राउंड-एबॉउट का एग्रीमेंट गवर्मेंट ऑफ इंडिया के साथ साइन हो गया है और वहां की डीपीआर्स आ गई हैं और उसका एप्रूवल लेकर उनका कार्य चलेगा। आपने टाइम बाउंड की बात एग्रीमेंट में कही थी। एग्रीमेंट 2012 तक के लिए हुआ है। आज की तारीख में जब एग्रीमेंट 2012 तक किया ताकि हमारी सारी योजना पूरी हो जाएंगी। आपने कहा कि 100 एमएलडी के लिए काम हो चुका है, 200 एमएलडी बाकी हैं जो ये 552 करोड़ रुपये आए है, उनसे 200 एमएलडी हैंडल हो सकेगी। वाराणासी की यह समस्या खत्म हो जाएगी।...(व्यवधान)

श्री राम कृपाल यादव : सर, पटना के बारे में एक भी जवाब नहीं आया।...(व्यवधान)

श्री नमोनारायन मीना :बोल रहे हैं। सबके बारे में बोल रहे हैं।...(व्यवधान)

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, ज़ीरो ऑवर कब होगा ?

उपाध्यक्ष महोदय :पहले यह खत्म होगा। इसके बाद ही ज़ीरो ऑवर शुरू होगा[R16]।

श्री नमोनारायन मीना : उपाध्यक्ष जी, जापान बैंक ऑफ इंटरनेशनल कॉरपोरेशन को हमने कानपुर, इलाहाबाद और लखनऊ - तीनों टाउन्स की समस्या के हल के लिये प्रपोज किया है। हमने वाराणसी के लिये प्राथमिकता से काम करने के लिये एग्रीमेंट कर दिया है और हम उस कार्य में लग रहे हैं। पटना

में गंगा एक्शन प्लान-2 चल रहा है। वहां इस संबंध में जितनी योजनायें चल रही हैं, उसमें पटना को शामिल किया गया है। उस प्लान के लिये जितना पैसा हमने दिया है, उसकी सूचना हम माननीय सदस्य को दे देंगे। 1986 में बीओडी की मात्रा 2 थी जो आज की तारीख में भी 2 ही है।

श्री राम कृपाल यादव : उपाध्यक्ष जी, मैं जानना चाहता हूं कि क्या पटना इस योजना में शामिल है या नहीं?

उपाध्यक्ष महोदय : पहले मंत्री जी का जवाब आने दीजिये।

श्री नमोनारायन मीना : श्री मोहन सिंह जी ने पी.ए.सी. रिपोर्ट के बारे में पुछा है। मैं उन्हें बताना चाहूंगा कि वह रिपोर्ट हमारे पास आ गई है और ATR पर कांम हो रहा है। इस संबंध में कुछ तो मैने बता दिया है, बाकी के बारे में कार्यवाही चल रही है। इसके अलावा गंगा पटना सिटी शिफ्टिंग के बारे में बात कही गई। हम उसे दिखवा लेंगे लेकिन यह कार्य हमारे विभाग के पास नहीं है। हमारे पास तो कंजर्वेशन का काम है। इरिगेशन का काम हम नहीं करते हैं। हमारा विभाग कंजर्वेशन, डाइवर्जन, सीवरेज या दूसरे कार्य देखता है। माननीय सदस्य ने वाराणसी में गंगा फेज़ 2 के लिये पैसा रिलीज किये जाने का सवाल उठाया था। मैं उन्हें बताना चाहूगा कि 9-10 करोड़ रुपया laying of relieving trunk sewer from Sigra crossing to Chaukaghat and prevention of overflow of sewerage from additional point sources के लिये खर्च किये गये हैं।

इसके अलावा जिन और कार्यों के लिये पूछा गया है, जो एक्सपैंडिचर्स आता है या जो सीवरेज ट्रीटमेंट या नॉन-सीवरेज ट्रीटमेंट का कार्य है, वह जल निगम या नगर निगम को दिया जायेगा। हमारे पास प्रोजैक्ट रिपोर्ट आ गई है, उसके आधार पर पैसा दिया जायेगा।

श्री खंडूड़ी जी ने प्रश्न उठाया कि जहां से गंगा जी निकलती है, वहां पर काफी प्रदूाण हो रहा है। हमारे पास भी ऐसी रिपोर्ट आई है। मैं माननीय सदस्य की इस बात से सहमत हूं। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट की यह पौलिसी है कि औरिजिन जहां से होता है, उस पर बैन लगा सकती है। कुछ राज्य सरकारों ने बैन लगा रखा है और कुछ राज्य सरकारें करना चाहती हैं। माननीय सदस्य ने इस ओर हमारा ध्यान दिलाया, मैं उसे दिखवा रहा हूं। उस पर जो भी काम रह गया है, हम करेंगे।...(व्यवधान[RB17])

13.00 hrs.

श्री रेवती रमन सिंह (इलाहाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इलाहाबाद का सांसद हूं और मैं इस समस्या से परिचित हूं जो मोहन सिंह जी ने उठाई है। मैं इनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन्होंने बड़ा सामयिक सवाल उठाया है। ...(व्यवधान)

मान्यवर, एक बात माननीय मंत्री जी के जवाब में आई है कि फर्स्ट फेज़ लागू होने के बाद 2000 एमएलडी गंदा पानी आता है जो पहले 1000 एमएलडी था। इससे बड़ा मज़ाक और क्या हो सकता है कि ज्यादा एमएलडी गंदा पानी गंगा में गिरने के बावजूद गंगा का बीओडी और साफ हो गया है। यह कैसा मज़ाक है?

दूसरी बात यह कि एक गंगा बोर्ड बना है जिसमें उत्तरांचल की सरकार, भारत सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार तीनों शामिल हैं। आज तक माननीय मंत्री जी उसकी एक भी मीटिंग नहीं कर पाए। समस्या कहां खड़ी होती है जैसा मोहन सिंह जी ने कहा कि दिल्ली पानी मांग रहा है सोनिया विहार प्लांट के लिए, जबकि उत्तर प्रदेश को पानी नहीं मिल पा रहा है क्योंकि उत्तरांचल सरकार वहां से पानी नहीं छोड़ रही है और अर्द्धकुम्भ मेला भी इस साल दिसम्बर में लगने वाला है। पिछले साल साधुओं ने स्नान भी नहीं किया। ...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आपका कोई प्रश्न है तो पूछें। मंत्री जी,आपका जवाब पूरा हो गया?

श्री नमोनारायन मीना : अभी तो बहुत बाकी है।

उपाध्यक्ष महोदय : रेवती रमन जी, आप बैठ जाएं। मंत्री जी को जवाब पूरा करने दें।

...(व्यवधान)

श्री नमोनारायन मीना : महोदय, गंगा एक्शन प्लान फर्स्ट फेज़ में 261 स्कीम्स ली थीं और उसमें 259 पूरी हो गई हैं। सैकेन्ड जो गंगा एक्शन प्लान है, उसमें 59 टाउन्स को लिया गया है। इसमें पांच स्टेट्स हैं - उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। अप्रूव्ड कॉस्ट 653 करोड़ रुपये है

और इसमें हमारी 268 स्कीमें ली हुई हैं। काम चल रहा है और 79 स्कीमें पूरी हुई हैं और जापान बैंक ऑफ इंटरनेशनल कोआपरेशन द्वारा काम चल रहा है। वाराणसी का हो गया, कानपुर का आएगा, लखनऊ का आएगा, इलाहाबाद का आएगा।

इतनी सारी स्कीमें चल रही हैं। मैंने जो आंकड़े दिये कि गंगा का एक पोर्शन है जिसमें कानपुर वगैरह है, वहां प्राबलम है। उसके लिए वाराणसी के बाद इलाहाबाद, लखनऊ आएंगे तो उनकी स्थिति उबरेगी। मैंने आपको पहले बताया कि पॉल्यूशन लोड बहुत है, जनसंख्या भी बढ़ रही है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से गंगा पॉल्यूट होती है। फील्ड का रनऑफ भी उसमें आता है, क्रीमेटोरिया से भी पॉल्यूशन होता है। मैं मोहम्मद साहब से सहमत हूं कि कितनी तरह की गंदगी लोग उसमें डालते हैं। यह केन्द्र सरकार को करना पड़ेगा, राज्य सरकार को करना पड़ेगा, म्यूनिसिपैलिटीज को करना पड़ेगा और आम जनता को भी नदियों के संरक्षण के लिए लाना पड़ेगा। पैसे का क्रन्च है यह हम मानकर चलते हैं। ...(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : इस बात कोहम सुनते सुनते थक गए।

श्री नमोनारायन मीना : थक गए? यह सब काम हो रहा है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि जो भी सुझाव माननीय सदस्यों ने दिये हैं, उन पर हम एक्शन लेंगे। धन्यवाद।